संख्या- 79/2018/3388(1)/33-3-2018-100(16)/2015

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 05 अक्टूबर, 2018**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-14 (सामान्य) में केन्द्रांश अवमुक्त होने की प्रत्याशा में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि रू. 164817.74 लाख अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पत्र संख्या-4/4262/2018-5/38/2018 दिनांक 25.09.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में मूल प्रावधान/अनुपूरक/ पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या-14 में प्रावधानित धनराशि रू. 895959.25 लाख के सापेक्ष रू. 705239.25 लाख की धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त धनराशि रू. 190720.00 लाख अवशेष है। योजनान्तर्गत अब तक निर्गत की गयी धनराशि सापेक्ष निर्धारित केन्द्रांश रू. 423143.55 लाख के सापेक्ष मात्र रू. 236791.97 लाख का ही केन्द्रांश प्राप्त हुआ है, जबकि अभी भी निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष रू. 186351.58 लाख का केन्द्रांश प्राप्त किया जाना अवशेष है। योजनान्तर्गत कुल निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष निर्धारित राज्यांश रू. 282095.70 लाख के सापेक्ष रू. 468447.28 लाख का राज्यांशनिर्गत कियागया है, जो कि निर्धारित राज्यांश से रू. 186351.58 लाख अधिक है।

इस अवशेष धनराशि में से अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त होने की प्रत्याशा में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि रू. 164817.74 लाख (रू. सोलह अरब अडतालीस करोड़ सत्रह लाख चौहत्तर हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979-10-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने पर उसके सापेक्ष राज्यांश के रूप में उक्त धनराशि केन्द्रांश की सीमा तक समायोजित की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण /सत्यापन हेतु पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(5) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(6) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमती नगर लखनउ में उ0प्र0 स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस.एस.एम.) के नाम से खोले गये खाता संख्या- 521302010060034 आई0एफ0एस0सी0 कोड यू बी आई एन 0552135 में अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(7) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन के बिन्दु- 13 के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के खाते में 15 दिन के अंन्दर स्थानान्तरित करते हुए संबंधित खाते से 15 दिन के अंदर संबंधित जनपदों को अवमुक्त किया जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा मैचिंग राज्यांश मद की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के खाते में अवमुक्त करने के उपरान्त संबंधित खाते से जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

(8) प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम हेतु पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि की उपयोगिता/समायोजन निदेशक, पंचायतीराज द्वारा किया सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मि-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101- पंचायती राज-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं - 0103-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना) (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-ई-2-957/X-18 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।

6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2

7- बजट प्रकोष्ठ /कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

8- एन0आई0सी0 की प्रति।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।